क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक - 19 | अक्तूबर 1-15, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-4

कृषि का संकट और समाधान

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित मीटिंग

मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) की ओर से संतोष कुमार ने यह कहते हुये मीटिंग की शुरूआत की कि "कृषि का संकट समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करता है और मज़दूर वर्ग के लिए यह एक बहुत चिंता का विषय है।" वे 11 सितंबर को "कृषि का संकट और समाधान" विषय पर आयोजित एक ऑनलाइन मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे।

मीटिंग में आमंत्रित वक्ता थे – मज़दूर एकता कमेटी के सचिव श्री बिरजू नायक, भारतीय किसान यूनियन एकता (डकौंदा) के अध्यक्ष श्री बूटा सिंह बुर्ज गिल, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.ई.एफ.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र दूबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. बी. सेठ और भारतीय रेलवे लोको रनिंगमैन ऑर्गनाइजेशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय पांधी।

संतोष कुमार ने वक्ताओं का परिचय देते हुए बताया कि श्री बूटा सिंह जी, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा एक साल से अधिक समय तक चलाये गये ऐतिहासिक विरोध संघर्ष में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने वक्ताओं का स्वागत करते हुये बताया कि वक्ताओं में बिजली और रेलवे में संघर्षरत मज़दूरों के प्रतिनिधियों सहित एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर भी शामिल हैं तथा देशभर से और विदेशों से भी सैकड़ों सहभागी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं।

सहभागियों में किसानों, मज़दूरों, युवाओं और महिलाओं सहित, विभिन्न पेशों से जुड़े लोग शामिल थे। इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर–प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों से मज़दूरों और किसानों की यूनियनों के कार्यकर्ताओं के साथ–साथ, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय प्रवासी मज़दूरों के कार्यकर्ता भी शामिल हुये थे।

श्री बिरजू नायक ने विस्तार से बताया कि कृषि पर बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीवादी घरानों के वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। कृषि के लिए ज़रूरी सभी वस्तुओं – बीजों, उर्वरक, बिजली, फ़सलों की ख़रीद क़ीमतों और किसानों को उनकी उपज के लिए मिलने वाले मूल्य तथा बाज़ार में उत्पादों की क़ीमतों तक पर इजारेदारों का वर्चस्व बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बड़े इजारेदार पूंजीवादी कॉरपोरेट घरानों के पास बड़े पैमाने पर भंडारण और परिवहन की सुविधाएं हैं और हक़ीक़त में, वे उन सभी क़ीमतों को निर्धारित कर सकते हैं, जिन क़ीमतों पर कृषि–उत्पादों को बाज़ार में ख़रीदा और बेचा जाता है। वे हिन्दोस्तान में ख़रीदे गए इन कृषि उत्पादों को और भी अधिक क़ीमत पर विश्व बाज़ार के लिये निर्यात कर सकते हैं और इससे अत्याधिक मुनाफ़े बना सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण के ज़रिये, इस हक़ीक़त को समझाया कि सरकार बड़े से बड़े पूंजीपतियों के हित में काम करती है। सरकार ने 13 मई को अचानक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और इस प्रतिबंध के चलते गेहूं के अधिकांश निर्यातकों पर पाबंदी लग गई, लेकिन, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को उस तारीख से पहले ही एक बैंक गारंटी जारी की गई थी ताकि वह जल्दी से जल्दी हिन्दोस्तान का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक बन सके।

श्री बिरजू नायक ने इस मीटिंग में कृषि में संकट के समाधान के लिये जो प्रस्ताव पेश किये उनमें थे – कृषि के लिए सभी ज़रूरी वस्तुओं को किसानों को रियायती क़ीमतों पर उपलब्ध कराने की गारंटी हो, मुनासिब और लाभकारी क़ीमतों पर सभी फ़सलों की ख़रीद सुनिश्चित की जाये, किसानों के कर्ज़े पर राहत दी जाये और राज्य द्वारा एक ऐसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई जाये जो देश में सभी खाद्य पदार्थों और बड़े पैमाने पर खपत होने वाली अन्य वस्तुओं की पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

श्री बूटा सिंह बुर्ज गिल ने पिछले 3–4 दशकों में हिन्दोस्तान में कृषि के बढ़ते संकट को समझाने के लिए वस्तु स्थिति से जुड़े कई तथ्य प्रस्तुत किए, जिनके कारण वर्तमान संकट पैदा हुआ है। उन्होंने बताया कि हरित–क्रांति ने देश को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सक्षम बनाया और इससे कृषि मज़दूरों की

शेष पृष्ठ 2 पर

रेलवे के ट्रेकमैनों का दिल्ली में विशाल विरोध प्रदर्शन

28 सितम्बर, 2022 को आल इंडिया रेलवे ट्रेक मेंटेनर्स यूनियन (ए.आई.आर.टी.यू.) की अगुवाई में हजारों की संख्या में आये, रेलवे के ट्रेकमैनों ने अपनी मांगों को लेकर नई दिल्ली स्थित जंतर–मंतर पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में भारतीय रेल के 17 मंडलों से लगभग ढाई हजार से ज्यादा महिला और पुरुष ट्रेकमैन शामिल हुए। प्रदर्शन का संचालन संगठन के महामंत्री श्री राकेश चंद्र वर्मा ने किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता श्री नरेंद्र पांचाल सहित 17 मंडलों से आए ट्रेकमैनों ने की।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, ए.आई.आर.टी.यू. के पदाधिकारियों ने घोषणा की कि ट्रेकमैनों के संघर्ष में यह प्रदर्शन ऐतिहासिक साबित होगा।

पदाधिकारियों ने लवासा कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि हर महीने ड्यूटी के दौरान 40 ट्रेकमैनों की मौत हो जाती है। साल में लगभग 500 ट्रेकमैनों की मौत होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा, जहां ड्यूटी के दौरान इतनी बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। केन्द्र सरकार यह दावा करती है कि भारतीय रेल विश्व स्तर की सुरक्षित रेल यात्रा प्रदान करती है। लेकिन रेल यात्रा को सुरक्षित करने वाले लाखों ट्रेकमैनों के जीवन की सुरक्षा करने में सरकार असफल रही है।

विभिन्न मंडलों से आए ट्रेकमैनों ने काम के दौरान आने वाली अपनी मुश्किलों को बताते हुए कहा कि भारतीय रेल प्रशासन ट्रेकमैनों पर अत्यधिक काम का दबाव डाल रहा है। हमें अपने जायज़ अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हमें अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। हमें अधिकारियों के निजी घरेलू कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। हमारे साथ गाली–गलौच व मारपीट होना आम बात है। यदि हम अपने अधिकारों की या नियम और क़ानून की बात करते हैं तो हमें दंडित करने के लिए झूठी चार्जशीट पकड़ा दी जाती है और परेशान किया जाता है।

उन्होंने कहा कि ट्रेकमैनों को इंजीनियरिंग गेटों पर गेटमैन की ड्यूटी दी जाती है। लगातार 12 घंटे की ड्यूटी होती है। गेट पर बने छोटे से कमरे में रोशनी, पानी व शौचालय की व्यवस्था नहीं होती। रेल प्रशासन को इसका आभास नहीं है कि गेटमैन की ड्यूटी एक इंसान कर रहा है, जिसे प्यास भी लगती है, शौचालय की आवश्यकता भी पड़ती है।

मज़दूर एकता कमेटी की एक टीम ने रेलवे ट्रेकमैनों के समर्थन में, प्रदर्शन में भाग लिया। मज़दूर एकता कमेटी की ओर से ट्रेकमैनों के संघर्ष के समर्थन में एक पर्चा जारी किया, जिसका आंदोलित ट्रेकमैनों ने बहुत स्वागत किया।

मज़दूर एकता कमेटी की ओर से संतोष कुमार ने कहा कि हमारा संगठन भारतीय रेल के ट्रेकमैनों के साथ भी खड़ा है। आपका जुझारू संघर्ष देश के सभी मज़दूरों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत है। हम आपके संघर्ष की जीत की पूरी कामना करते हैं। हम आपकी जायज़ मांगों का समर्थन करते हैं। मज़दूर एकता कमेटी सरकार से मांग करती है कि ट्रेकमैनों की मांगों को बिना शर्त पूरा करे और भारतीय रेल में किये जा रहे निजीकरण पर तुरंत रोक लगाए।

धरने को संबोधित करने वालों में थे – श्री कांता राजू (राष्ट्रीय महामंत्री), श्री राम नरेश पासवान (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष), पंकज राजपूत (राष्ट्रीय सहायक महामंत्री, सह संचालक), श्री राजेंद्र कौशिक (राष्ट्रीय सहायक महामंत्री), श्री रवि यादव (अध्यक्ष इलाहाबाद मंडल), श्री शुभम उपाध्याय (मीडिया प्रभारी बिलासपुर), उपेन्द्र यादव (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), राजेश मौर्या (मंडल

शेष पृष्ठ 3 पर

अंदर पढ़ें

- राडिया टेप्स से किस बात का पर्दाफाश हुआ 3
- पाठकों की प्रतिक्रिया 3

कृषि का संकट और समाधान

पृष्ठ 1 का शेष

स्थिति में भी सुधार हुआ। हालांकि, इसने उन फ़सलों को बढ़ावा दिया, जिनके लिये अधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, ऐसी फ़सलों को प्राथमिकता दी गयी जिनमें कीड़ों और बीमारियों का ख़तरा अधिक होता है। इसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता भी नष्ट हो गयी और इसने कई फ़सलों को पैदा करने की मिट्टी की क्षमता को भी बर्बाद कर दिया। कई किसानों ने यह सपना देखा था कि हरित क्रांति से उन्हें अधिक लाभ होगा। लेकिन हरित क्रांति ने कृषि के संकट को हल करने की बजाय पंजाब में कृषि और किसानों को बरबाद और नष्ट कर दिया।

केंद्र सरकार ने तीन किसान–विरोधी क़ानून लाने की कोशिश की थी, जिनके द्वारा कृषि पर हिन्दोस्तानी और विदेशी कॉरपोरेट घरानों की पकड़ को और मजबूत किया जा सके। हमने एक साल से भी अधिक समय तक कड़ा संघर्ष किया और पूरे पंजाब और अन्य राज्यों में किसानों को संगठित किया। हम अपने संघर्ष की बदौलत सरकार को क़ानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करने में सफल भी रहे। लेकिन सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर हमारे आंदोलन को वापस लेने की शर्त के रूप में जो आश्वासन दिए थे, उनमें से हमारी किसी भी मांग को सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। ऐसे हालातों में हमें फिर से आंदोलन करना होगा। संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमें संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) को मजबूत करना होगा।

उन्होंने बताया कि किसानों के लिए कर्ज़ राहत, उनकी एक प्रमुख मांग है। कृषि के लिए राज्य को एक समग्र योजना बनाने की आवश्यकता है कि – किस जगह पर कितना और क्या उगाया जाना है, राज्य की ख़रीद एजेंसियां किस क़ीमत पर उपज को खरीदेंगी, भंडारण तथा परिवहन और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कैसी होगी, आदि। केवल एम.एस.पी. की बात करना ही काफी नहीं है, क्योंकि इस समय एम.एस.पी. सिर्फ गेहूं और धान के लिए ही दी जा रही है, सरकार द्वारा अन्य सभी कृषि उत्पादों को भी लाभकारी क़ीमतों पर खरीदने की आवश्यकता है। जब तक ऐसे क़दम नहीं उठाए जाते, कृषि के संकट का समाधान नहीं हो सकता। बूटा सिंह बुर्ज गिल ने किसानों के साथ मज़दूर वर्ग की मजबूत एकता के लिए एक ज़ोरदार अपील की। यदि कृषि और उद्योग मिलकर पूरे समाज की भलाई के दृष्टिकोण से काम करें, तभी हम इस संकट के समाधान की आशा कर सकते हैं।

मीटिंग को संबोधित करते हुए श्री शैलेन्द्र दूबे ने उस लड़ाकू संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो संघर्ष विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को वर्तमान स्वरूप में संसद में पेश होने से रोकने के लिए पूरे देश में बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। विधेयक का उद्देश्य है राज्य के डिस्कॉम के वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल करके निजी कंपनियों को बिजली वितरण पर कब्ज़ा करने के लिए सक्षम बनाना। इजारेदार पूंजीपति चाहते हैं कि इस विधेयक को तुरंत पारित किया जाए, ताकि पूरे देश में बिजली वितरण पर उनके कब्ज़े को सुनिश्चित किया जा सके ताकि वे इससे भारी मुनाफ़ा बना सकें।

उन्होंने बताया कि किसानों के लिए इस बिजली संशोधन विधेयक के विनाशकारी परिणाम होंगे। क्योंकि सिंचाई के लिये अपने पंप सेट और अन्य कृषि मशीनरी के संचालन के लिए बिजली का खर्च नहीं उठा सकेंगे, उन्हें अत्याधिक क़र्ज़, दिवालियेपन और बर्बादी की ओर धकेल दिया जाएगा। किसानों के संघर्ष को सांझा करते हुए, उन्होंने कृषि की लागत वस्तुओं पर अधिक से अधिक राज्य सब्सिडी की मांग की। उन्होंने बिजली संशोधन विधेयक को किसान–विरोधी, समाज–विरोधी घोषित करते हुए, विधेयक को वापस लेने की मांग के साथ एकजुट होकर, संगठित संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की कि पूरे देश के बिजली कर्मचारी अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, 23 नवंबर को नई दिल्ली में एक विशाल विरोध प्रदर्शन में एक साथ आएंगे।

प्रोफेसर बी. सेठ ने कृषि के संकट को समझाने और उसके समाधान का प्रस्ताव पेश करने के लिए पावर–प्वाइंट प्रस्तुति पेश की। उन्होंने कहा कि इस संकट के दो पहलू हैं। अधिकांश किसान सम्मानजनक जीवन यापन के लिए कृषि उत्पादों से पर्याप्त आमदनी अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही शहरों में मज़दूरों का एक बहुत बड़ा तबका, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन को जुटा पाने में असमर्थ हैं। एक किसान परिवार की औसत आय 5,000 रुपये प्रति माह से कम है। उन्होंने बताया कि इन हालतों के कुछ प्रमुख कारण हैं – बीज, उर्वरक, डीजल, बिजली, आदि जैसे कृषि के लिये आवश्यक लागत वस्तुओं की क़ीमतें बहुत ज्यादा हैं, किसानों द्वारा उपजाये गये कृषि उत्पादों के लिए ख़रीद मूल्य बहुत ही कम है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की कमी और अधिकांश किसानों पर कर्ज़ का बढ़ता बोझ है। उन्होंने बहुप्रचारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) का पर्दाफ़ाश करते हुये बताया कि इसका उद्देश्य है किसानों को राहत पहुंचाने के बहाने निजी बीमा कंपनियों को भारी मुनाफ़ा कमाने में सक्षम बनाना।

प्रोफेसर बी. सेठ ने पूरी कृषि प्रक्रिया पर हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीवादी घरानों के बढ़ते प्रभुत्व पर भी प्रकाश डाला। पूंजीवादी घरानों का यह प्रभुत्व एक तरफ किसानों को तबाह कर रहा है और दूसरी तरफ शहरों में मज़दूरों के बीच बढ़ती भुखमरी से उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है।

श्री संजय पांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि सरकारी नीतियां बहुसंख्य लोगों के हित में काम नहीं करती हैं, चाहे वे शहरों में हों या गांवों में। इन नीतियों का उद्देश्य, किसानों और मज़दूरों, दोनों को लूटकर अपनी तिजोरियों को भरने में बड़े कॉरपोरेट घरानों को सक्षम बनाना है। उन्होंने सुझाव दिया कि कैसे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े मज़दूर और विशेषज्ञ, किसान यूनियनों को पेशेवर सहायता प्रदान कर सकते हैं। भारतीय रेल में इंजन चालकों की यूनियन के एक कार्यकर्ता के रूप में, जो रेलवे के निजीकरण के सरकार के प्रयासों का जुझारू विरोध कर रहे हैं, उन्होंने मज़दूरों और किसानों के एकजुट संघर्ष का आह्वान किया।

मुख्य वक्ताओं के विचार प्रस्तुत हो जाने के बाद, चर्चा में दस से अधिक सहभागियों ने अपनी बातें रखीं।

तमिलनाडु से वर्कर्स यूनिटी मूवमेंट के प्रतिनिधि ने, संसद में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की पकड़ से मुक्त होने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो हमें विभाजित करने और झूठे वादे करके हमें बेवकूफ़ बनाने के इरादे से काम करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टियां इजारेदार पूंजीवादी घरानों के मुनाफ़ों को अधिकतम करने के लिए लगातार काम करती आयी हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण के अपने एजेंडे के इर्द–गिर्द मज़दूरों और किसानों की एकता बनाने का आह्वान किया। जिसमें कॉरपोरेट घरानों का मुनाफ़ा नहीं, बल्कि पूरे समाज का कल्याण सर्वोपरि होगा।

राजस्थान में किसान मज़दूर व्यापारी संघर्ष समिति से जुड़े हनुमान प्रसाद शर्मा ने कृषि के संकट पर विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि मज़दूरों और किसानों के लिए एकमात्र समाधान अपने एक ही दुश्मन, इजारेदार कॉरपोरेट घरानों के ख़िलाफ़ एकजुट होना है, जिन घरानों के खुदगर्ज हितों की रक्षा हिन्दोस्तानी राज्य करता है। मज़दूरों और किसानों को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो सभी को सुख और सुरक्षा की गारंटी दे सके।

ग़दर इंटरनेशनल, ग्रेट–ब्रिटेन के सलविंदर ढिल्लों ने बताया कि ब्रिटेन में मज़दूरों और हिन्दोस्तान में किसानों और मज़दूरों का संघर्ष, सबसे बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों की पूंजीवादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ संघर्ष है। उन्होंने आह्वान किया कि इस संकट से निकलने का एकमात्र रास्ता, मज़दूरों और किसानों के हाथों में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के संघर्ष तेज़ करना।

कामगार एकता कमेटी के एस. दास ने मज़दूरों और किसानों का एक शक्तिशाली और एकजुट आंदोलन खड़ा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मज़दूरों और किसानों को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी। कृषि के संकट और समाज की सभी उत्पादक शक्तियों की तबाही सहित, हिन्दोस्तानी समाज के गहरे संकट को हल करने का यही एकमात्र तरीक़ा है।

अखिल भारतीय किसान मज़दूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र पूरे समाज के हित में काम करे, इसको सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीक़ा है मज़दूरों और किसानों के राज को स्थापित करने के लिए काम करना।

अन्य सहभागियों ने कृषि के सभी पहलुओं पर इजारेदारी का नियंत्रण, डेयरी किसानों की समस्याओं, बढ़ते क़र्ज़ और किसान आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं, छोटी भूमि के मालिकों की दरिद्रता और बढ़ती भूमिहीनता के बारे में अपने विचार रखे। दिल्ली के एक औद्योगिक क्षेत्र के नौजवान कार्यकर्ता ने शहरों में दिहाड़ी मज़दूरों के बीच आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या पर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट का हवाला दिया। मज़दूर और किसान दोनों आजीविका की भयानक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और इसके लिए केवल पूंजीवादी व्यवस्था ही ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हम मज़दूर और किसान, जो समाज की संपत्ति पैदा करते हैं, हमें समाज का मालिक बनना होगा।

मीटिंग में हुई चर्चा का सारांश पेश करते हुए, संतोष कुमार ने वक्ताओं और सभी सहभागियों को उनकी बहुमूल्य प्रस्तुतियों और सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। इस असूल को क़ायम रखते हुए कि "एक पर हमला सब पर हमला" है। उन्होंने घोषणा की कि मज़दूर एकता कमेटी ऐसी और भी कई मीटिंगें आयोजित करती रहेगी। निष्कर्ष में उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हमारा उद्देश्य, मज़दूरों और किसानों को एक सांझे मंच पर लाना है ताकि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाये, जो मज़दूरों, किसानों तथा सभी शोषित–उत्पीड़ित लोगों के हितों व उनकी सुख और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

http://hindi.cgpi.org/22633

निजीकरण के विरोध में हाल के कुछ प्रकाशन

भारतीय रेल का निजीकरण हमें मंजूर नहीं

क़ीमत 20 रूपये
हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध

बैंकों का विलय और निजीकरण

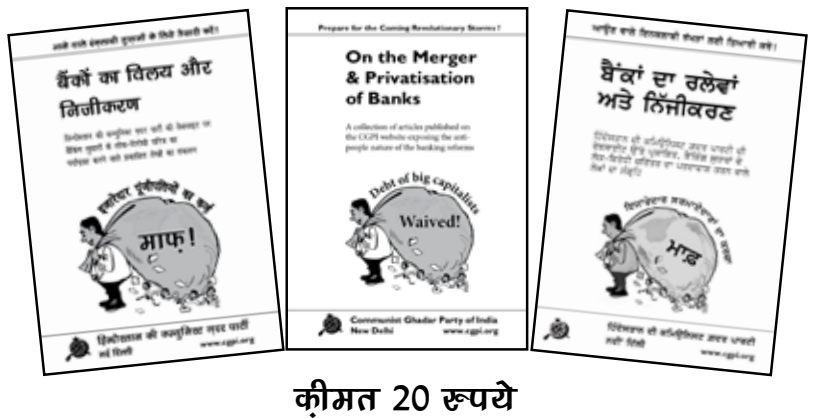

क़ीमत 20 रूपये
हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध

राडिया टेप्स से किस बात का पर्दाफ़ाश हुआ

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने 21 सितंबर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसे राडिया टेप्स में कुछ भी आपराधिक नहीं मिला है। इन टेप्स में राज्य की विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए टेलीफोन की बातचीत का रिकॉर्ड है। इनमें नीरा राडिया जो कि कई प्रमुख इजारेदार घरानों का प्रतिनिधित्व करती है। वह अपने मालिकों के साथ–साथ, विभिन्न पार्टियों के मंत्रियों और राजनेताओं के साथ भी बातचीत करती सुनाई देती है।

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. को इन टेप्स की जांच करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी क "राडिया की बातचीत दिखाती है कि निजी उद्योग सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने निजी हितों को पूरा कर रहे हैं"।

सी.बी.आई. का रुख़ बताता है कि इस पूरे मामले को अब चुपचाप दबाया जा सकता है। इस संदर्भ में, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी द्वारा 18 दिसंबर, 2010 को प्रकाशित लेख के कुछ अंशों को नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। लेख का शीर्षक है – राडिया टेप्स से किस बात का पर्दाफ़ाश हुआ : इजारेदार पूंजीवादी घरानों की हुक्मशाही ही बहु–पार्टीवादी प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र की हक़ीक़त है।

उद्धरण

राडिया टेप्स से स्पष्ट होने वाली एक अहम सच्चाई यह है कि इजारेदार पूंजीपति केन्द्र और राज्यों में सरकार बनाने वाली पार्टियों के गठबंधन को ही नहीं निर्धारित करते, बल्कि किसी ख़ास विभाग का मंत्री कौन बनेगा, यह फ़ैसला भी इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है। टेप्स से जाना जाता है कि दूसरी संप्रग सरकार में कौन–सा द्रमुक नेता टेलिकॉम मंत्री बनेगा, इस फ़ैसले को प्रभावित करने के लिये टाटा समूह राडिया को पैसे दे रहा था।

हमारे देश में जो बहु–पार्टीवादी प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र मौजूद है, उसके बारे में यह प्रचार किया जाता है कि यह जनता द्वारा, जनता के लिये, जनता का शासन है। परन्तु राजनीतिक प्रक्रिया में अधिकतम लोगों की भूमिका बहुत ही कम होती है और वह भी सिर्फ मतदान के दिन तक। मुट्ठीभर अति अमीर और शक्तिशाली इजारेदार पूंजीपति यह निर्धारित करते हैं कि कौन–सी पार्टी या गठबंधन सरकार बनायेगी। वे सीधे तौर पर यह चयन करते हैं कि किसी खास मंत्रालय का मंत्री कौन होगा। पूंजीपति, नेताओं को पैसे देते हैं और जिसके बदले में नेता सत्ता में आ जाने के बाद पूंजीपतियों के हितों में काम करते हैं। इस तरह वर्तमान राजकीय इजारेदार पूंजीवादी व्यवस्था में नियमित तौर पर मंत्री और अधिकारी खास कंपनियों को लाईसेंस और परमिट देते हैं।

21 सितंबर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय को सी.बी.आई. ने सूचित किया कि उसे राडिया टेप्स में कुछ भी आपराधिक नहीं मिला है। ... 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. को इन टेप्स की जांच करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी क "राडिया की बातचीत दिखाती है कि निजी उद्योग सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने निजी हितों को पूरा कर रहे हैं"।

इजारेदार पूंजीपति "विपक्ष" की पार्टियों को भी पैसे देते हैं। इसके बदले में, विपक्ष के नेता भी पूंजीपतियों के हित में तरह–तरह के काम करते हैं। इन मुट्ठीभर शोषकों की हुकूमत को सिर्फ वैधता प्रदान करने के लिये चुनाव करवाये जाते हैं।

राडिया टेप्स से हमें कुछ झलक मिलती है कि सरकार की नीति कैसे बनायी जाती है। जांच संस्थानों को टेप्स पर रिकार्ड की गई चर्चाओं का संकलन करते हुये यह मानना पड़ा है कि विभिन्न सरकारी विभागों – टेलिकॉम, पेट्रोलियम और गैस, रक्षा, एयर लाइन इत्यादि – के कामकाज पर इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा अपने दलालों के ज़रिये चर्चा होती है और तरह–तरह के दांवपेच किये जाते हैं ताकि एक पूंजीपति अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर अपने हितों को बढ़ावा दे सके। कहा जाता है कि सरकारी नीतियां "राष्ट्र हित" में बनायी जाती हैं, परन्तु हक़ीक़त में ये नीतियां इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिये बनायी जाती हैं।

पूंजीपति वर्ग के प्रचार के अनुसार, बीते दो दशकों में "मुक्त बाज़ार" सुधारों के चलते, "लाइसेंस परमिट राज" के पुराने भ्रष्ट तौर–तरीक़े ख़त्म हो गये हैं। यह प्रचार किया जाता है कि 1991 में तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई तथाकथित सुधार प्रक्रिया के ज़रिये व्यवस्था में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही आ गई है। परन्तु राडिया टेप्स के खुलासों से पता चलता है कि शासकों के ये दावे कितने खोखले हैं।

पूंजीवाद के विकास के वर्तमान पड़ाव की विशेषता ऊपर से नीचे तक इजारेदार बड़े पूंजीपतियों का प्रभुत्व, परजीविता तथा भ्रष्टाचार है। इस व्यवस्था के चलते, "मुक्त स्पर्धा" या बराबर के खिलाड़ी हो ही नहीं सकते। बाज़ार तथा राज्य के संस्थानों पर इजारेदार पूंजीपतियों का पूरा बोलबाला है। तथाकथित बाज़ार उन्मुख सुधारों के ज़रिये इजारेदार पूंजीपतियों के लिये नये–नये मौके पैदा हुये हैं, ताकि कुछ इजारेदार पूंजीपति दूसरों को पीछे धकेलकर खुद आगे बढ़ सकें, जिसके कारण पूंजी और सत्ता हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा हद तक संकेन्द्रित होती जाती है।

नेहरूवी "समाजवादी नमूने के समाज" के दौरान और हाल की उदारीकरण और निजीकरण की अवधि, दोनों ही अवधियों के दौरान हमारे देश में जो व्यवस्था विकसित हुई है, वह राजकीय इजारेदार पूंजीवाद ही थी। इस व्यवस्था में इजारेदार पूंजीपति केन्द्रीय राज्य पर नियंत्रण करते हैं और केन्द्रीय राज्य इजारेदार कंपनियों के हित में काम करता है। समय के साथ–साथ, इजारेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है जिसके कारण हरेक सौदे में बहुत बड़ी बाजियां लगाई जाती हैं। कुछ नये पूंजीवादी समूह आगे आये हैं और विकसित हुये हैं, जबकि कुछ पुराने पूंजीवादी समूह पीछे हटने को मजबूर हुये हैं। नेताओं और बड़े पूंजीपतियों के बीच के संबंध दिन–ब–दिन बढ़ते जा रहे हैं।

पूंजीपति वर्ग यह प्रचार करता है कि कुछ सुधारों या छोटे–मोटे क़दमों से वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को साफ और भ्रष्टाचार रहित बनाया जा सकता है। परन्तु सच्चाई तो यह है कि सिर्फ़ मज़दूर वर्ग की अगुवाई में क्रान्ति ही मुट्ठीभर शोषकों के भ्रष्ट और परजीवी शासन को ख़त्म कर सकती है। पूंजीवादी लोकतंत्र की जगह पर आधुनिक मज़दूर वर्ग की अगुवाई में मेहनतकश जनसमुदाय का शासन यानि श्रमजीवी लोकतंत्र स्थापित कर सकती है।

समय के साथ–साथ पूंजीवादी लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट और दमनकारी होता जायेगा। इसका अन्त तभी होगा जब मज़दूर वर्ग किसानों के साथ गठबंधन बनाकर अपने अतीत से नाता तोड़ेगा और आधुनिक लोकतंत्र की अगुवाई करेगा। वह आधुनिक लोकतंत्र मज़दूर वर्ग की अगुवाई में मेहनतकश जनसमुदाय का शासन होगा, जिसमें कोई भी सरकारी सेवक अपने पद का फ़ायदा उठाकर निजी हितों की सेवा करने की हिम्मत नहीं करेगा।

राडिया टेप्स से स्पष्ट होने वाली सबसे अहम बात यह है कि पूंजीवादी लोकतंत्र और उसके बारे में सारे भ्रमों से नाता तोड़ना आवश्यक है।

http://hindi.cgpi.org/22627

रेलवे के ट्रेकमैनों का दिल्ली में विशाल विरोध प्रदर्शन

पृष्ठ 1 का शेष

महामंत्री एनसीआर), सुनील शुक्ला (मंडल उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे), आदि। इनके अलावा, विभिन्न मंडलों से आए ट्रेकमैनों ने भी अपनी बातें रखीं।

एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को सौंपा।

ज्ञापन में ट्रेकमैनों ने मांग की कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाये, रेलवे में ट्रेक मेंटेनर्स की यूनियन को मान्यता दी जाये, ट्रेकमैन के खाली पदों पर हर साल भर्ती की जाये, ट्रेकमैन और गेटमैन की ड्यूटी को 8 घंटे निर्धारित किया जाये, ग्रेड पे को बढ़ाकर 4200 रुपये किया जाये, ट्रेकमैनों के परिजनों को मेडिकल और पास सुविधा प्रदान की जाये, अकुशल ट्रेकमैनों के लिये रिस्क अलाउंस लागू किया जाये, ट्रेकमैन की मौत होने पर 1 करोड़ गेच्युटी दी जाये और शौचालय व आरामकक्ष की सुविधायें उपलब्ध कराई जायें, आदि।

http://hindi.cgpi.org/22635

मज़दूर एकता लहर (इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : http://www.hindi.cgpi.org, **अंग्रेजी** : http://www.cgpi.org
पंजाबी : http://www.punjabi.cgpi.org, **तामिल** : http://www.tamil.cgpi.org
ई मेल : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

पाठकों की प्रतिक्रिया

महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराध

संपादक महोदय,

मज़दूर एकता लहर में प्रकाशित लेख – हिन्दोस्तानी राज्य पूरी तरह से सांप्रदायिक है, आइए हम सब मिलकर इंसाफ करने के अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं – को पढ़कर मैं इस पर अपने विचार रखना चाहती हूं।

हिन्दोस्तान में और दुनिया में महिलाओं पर हिंसा, अपराध व शोषण खूब तेज़ी से बढ़ रहा है। बिलकीस बानो आज का जीता–जागता उदाहरण है। जो उसके साथ हुआ वह बहुत ही शर्मनाक बात है। परन्तु यह कोई इकलौती घटना नहीं है। अपने देश में बहुत वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। आज भी महिलायें पितृसत्ता, घेरलू हिंसा, यौन हमलों, रीति–रिवाज़ों और जाति–प्रथा, आदि की शिकार बनती रहती हैं, जबकि हमारे देश में सत्ताधारी लोग महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें करते हैं?

हिन्दोस्तान में पिछले साल बलात्कार के 31,677 मामले रिकार्ड किये गये हैं, यानी औसतन 86 प्रतिदिन या हर घंटे में 49 महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध होते हैं। यह जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) से मिली है। अपने देश में ऐसे ही बहुत से मामलों को कहीं दर्ज ही नहीं किया जाता।

हमारी महिलाओं को सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आंतकवाद का बेहद नृशंस तरीक़े से शिकार बनाया जाता है जैसा कि 2002 में गुजरात में हुये जनसंहार में या 1984 में हुये जनसंहार में तथा मणिपुर व कश्मीर में फ़ौजी शासन में तमाम अत्याचार होते आ रहे हैं।

महिलाओं की हालतें इतनी र्ददनाक क्यों हैं? जैसा कि लेख में बताया गया है, हम महिलाओं को समाज में हो रही हर प्रकार की नाइंसाफी के ख़िलाफ़ सघर्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर सघर्ष करना होगा और पुरानी राज्य व्यवस्था को उखाड़कर फैंकना होगा तथा एक नये समाज की रचना करनी होगी। यही महिला मुक्ति का सही रास्ता है।

आपकी पाठक
सना, दिल्ली

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Oct, 2022 Date of publish - 1 Oct, 2022

To
.....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

भिवंडी में करघा मज़दूरों की विजय सभा

भिवंडी में 12 सितंबर, 2022 को लालबावटा पावर लूम वार्पर और असंगठित कामगार संगठन के बैनर तले "कामगार संघर्ष सभा" का आयोजन किया गया था। यह सभा उन मज़दूरों की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई थी, जिन्होंने एक संयुक्त और दृढ़तापूर्ण संघर्ष के बाद अपने मासिक वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि हासिल की थी।

वक्ताओं में महाराष्ट्र के दहानू से विधायक व सीटू के राज्य सचिव, कॉमरेड विनोद निकोल और सोलापुर के पूर्व विधायक व मज़दूर नेता, कॉमरेड नरसाया एडम मास्टर थे। लोक राज संगठन (एल.आर.एस.) के एक प्रतिनिधि को भी सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

करघा मज़दूरों और बीड़ी मजदूरों के नेता कॉमरेड सुनील चव्हाण ने मज़दूरों की एकता और उनके समर्थन की सराहना की और सभा का संदर्भ समझाया। भिवंडी में जब करघा मज़दूर उचित मज़दूरी और सुविधाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, तभी करघा मालिकों के गुंडों ने उनकी यूनियन के कार्यालय में प्रवेश किया और उन पर हमला कर दिया। परन्तु, मज़दूरों

ने एकजुट होकर गुंडों को भगा दिया और अब मालिकों के पास बातचीत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

हॉल में मौजूद 1,000 महिलाएं, पुरुष और नौजवान, कॉमरेड सुनील के साथ सहमत थे। उन्होंने "लड़ेंगे जीतेंगे!", "इंक़लाब ज़िंदाबाद!", "हमारा हक़ लड़के लेंगे!" और "मलिकों की दादागिरी नहीं चलेगी!", आदि जुझारू नारे लगाए। काम का दिन होने की वजह से मज़दूरी का नुक़सान होने की संभावना और बारिश होने के बावजूद, इस सभा में भारी संख्या में मज़दूर शामिल हुए थे।

कॉमरेड नरसाया एडम मास्टर ने गुंडों से लड़ने वाले 400 मज़दूरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम हमेशा जीतेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे हैं; हम अपना पसीना बहाते हैं। जो कुछ भी पैदा होता है वह मेहनतकशों के श्रम के कारण होता है। हम मालेगांव, नासिक, सोलापुर, आदि अनेक इलाकों में संघर्ष कर रहे हैं।

लोक राज संगठन की प्रतिनिधि सुश्री तृप्ति ने बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और मज़दूरों की उपस्थिति की सराहना की और कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें न्यूनतम मज़दूरी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की मांग के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज लड़े थे? यह वह समाज नहीं है जिसे हम चाहते हैं। आज हर वस्तु के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। हमारी सार्वजनिक संपत्तियों को सस्ते में सबसे अमीरों को बेचा जा रहा है। उनके पास हिन्दोस्तान के मेहनतकशों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने अधिकारों के लिए किये गये मज़दूरों के इस संघर्ष के लिये लोक राज संगठन का समर्थन व्यक्त किया।

कॉमरेड निकोल ने कहा कि वे हमें हिंदू और मुस्लिम के रूप में बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मज़दूरों के संघर्ष के लिए अपने समर्थन की घोषणा की और कहा कि वे इसके बारे में भिवंडी के विधायक से बात करेंगे और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे कि ट्रेड यूनियनों, उनके नेताओं और मज़दूरों पर हमले कैसे हो रहे हैं।

http://hindi.cgpi.org/22624

पाठकों की प्रतिक्रिया

अमरीकी साम्राज्यवादियों के अपराध

प्रिय संपादक,

11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी के अवसर पर प्रकाशित लेख सटीकता से दर्शाता है कि "संयुक्त राज्य अमरीका वही राज्य है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, सर्व–सम्मति से स्थापित किये गए, राज्यों के आपसी संबंधों के हर नियम और मानदंड का बार–बार उल्लंघन किया है।"

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से अमरीका द्वारा आयोजित युद्धों, सशस्त्र हस्तक्षेपों और तख़्तापलट की कार्यवाइयों की सूची मैं नीचे दे रहा हूं। मैं मानता हूं कि यह सूची भी शायद संपूर्ण नहीं है।

- 1946 : अमरीका ने फिलीपींस और दक्षिण कोरिया पर कब्ज़ा किया।
- 1947 : फासीवाद विरोधी ताक़तों को दबाने के लिए अमरीका ने सशस्त्र बलों को यूनान में उतरा।
- 1948–49 : अमरीकी सेना ने चीन के मुक्ति संग्राम में हस्तक्षेप किया और ताइवान की स्थापना में मदद की।
- 1949 : अमरीकी खुफिया ऐजेंसी सी.आई.ए. ने सीरिया में तख़्तापलट आयोजित किया।
- 1950–53 : कोरियाई युद्ध को चलाया।
- 1953 : अमरीकी खुफिया ऐजेंसी सी.आई.ए. ने ईरान में तख़्तापलट आयोजित किया।
- 1954 : अमरीका ने ग्वाटेमाला पर आक्रमण किया और वहां कठपुतली शासन स्थापित किया।
- 1955–75 : वियतनाम पर युद्ध किया।
- 1961 : बे ऑफ पिग्स का क्यूबा पर आक्रमण।
- 1962 : थाइलैंड में कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए अमरीकी नौसैनिकों को तैनात किया।
- 1965 : अमरीकी सेना ने डोमिनिकन गणराज्य पर कब्ज़ा किया।
- 1965–67 : इंडोनेशिया में अमरीकी सशस्त्र फासीवादी शासन स्थापित किया, जिसने लाखों कम्युनिस्टों को मार डाला।
- 1973 : योम किप्पुर युद्ध में अमरीका ने इज़रायल की सहायता की।
- 1973 : सी.आई.ए. ने चिली में एक सैन्य तख़्तापलट का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रपति ओलेंदे की मृत्यु हो गई।
- 1979–88 : सी.आई.ए. ने अफ़ग़ानिस्तान में छद्म युद्ध छेड़ा।
- 1981–86 : सी.आई.ए. ने निकारागुआ में छद्म युद्ध छेड़ा।
- 1988 : अमरीकी सेना ने पनामा पर कब्ज़ा किया।
- 1991–93 : ईरान पर हमला करने के लिये अमरीका ने इराक को हथियारों से लैस किया।
- 1994 : अमरीका ने हैती पर आक्रमण किया।
- 1995 : अमरीका के नेतृत्व में नाटो ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर बमबारी की।
- 1998 : इराक पर अमरीकी बमबारी तथा अफ़ग़ानिस्तान व सूडान पर मिसाइली हमले।
- 1999 : कोसोवो के युद्ध में अमरीकी हस्तक्षेप।
- 2001–21 : अमरीका ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला और कब्ज़ा किया।
- 2002 के बाद : अमरीका ने यमन में सऊदी हस्तक्षेप का समर्थन किया; पाकिस्तान में ड्रोन हमले किये।
- 2003 के बाद : अमरीका ने इराक पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया; सद्दाम हुसैन की हत्या कर दी।
- 2007 : सोमालिया में अमरीकी सैनिक हस्तक्षेप।
- 2011 : अमरीका के नेतृत्व वाले नाटो सेना ने लीबिया पर हमला किया; गद्दाफी की हत्या की।
- 2012 के बाद : अमरीका ने सीरिया में तथाकथित विद्रोहियों को हथियार दिये।
- 2014 : सी.आई.ए. ने यूक्रेन में तख़्तापलट किया और अमरीका समर्थक सत्ता स्थापित की।

इसमें कोई शक नहीं है कि अमरीकी साम्राज्यवाद राज्यों के आपस बीच सभ्य संबंधों और राष्ट्रीय संप्रभुता के सभी स्वीकृत मानदंडों का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता है। यह युद्ध करके और दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करके पनपता है। यह विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है।

आपका,
मुकुंद, विजयवाड़ा

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626,
ब्रांच नं.–00974, IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com